मध्य प्रदेश में खनिजों की संभावना का पता लगाने के लिये किये गये सर्वेक्षण

371. श्री अजीत जोगी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1987-88 और 1989 से अब तक मध्य प्रदेश में खनिजों की संभावनाओं की खोज के लिए कराए गए सर्वेक्षणो के परिणाम सामने आए हैं; और

(ख) उपरोक्त सर्वेक्षणों के आधार पर खनिजो के दोहन के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) इस अवधि मे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा मध्य प्रदेश भूविज्ञान एवं खान निदेशालय ने मध्य प्रदेश में कोयला, आधार-धातुओं, स्वर्ण, फास्फोराइट, मोलिब्डेनम, हीरा, टिन अयस्क, क्रोमाइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा रॉक फास्फेट के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण किये हैं । इन सर्वेक्षणों के आधार पर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सुहागपुर, कोरबा, रायगढ़ तथा तत्ता-पानी-रामकोला कोयला क्षेत्रों में कोयले के 1575 मिलियन टन अतिरिक्त भंडारों का आकलन किया है । मध्य प्रदेश भूविज्ञान एवं खान निदेशालय ने रायपुर तथा दुर्ग जिलो मे 108 मिलियन टन चूना पत्थर, रायपुर जिले के सोना खान क्षेत्र में 1440 कि० ग्रा० स्वर्ण, मांडला जिले में 60 मिलियन टन बजरी टिन अयस्क और 8 मिलियन टन डोलोमाइट तथा शाहडोल जिले में 24 मिलियन टन कोयला भंडारो का आंकलन किया है ।

(ख) इस प्रकार के प्रारंभिक सर्वेक्षणो के आधार पर खनिजो के विदोहन की योजना नहीं बनायी जा सकती ।

Enhancement of conveyance allowance to the Physically Handicapped Employees

@372. SHRI N. RAJANGAM : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any conveyance allowance is given to the physically handicapped persons in Government service;

(b) if so, what is the rate of such allowance; and

(c) whether Government propose to enhance the amount of such allowance ?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Blind and orthopaedically handicapped Central Government employees having permanent partial disability as well as those suffering from hunchback disability of specified degree are entitled for the grant of conveyance allowance.

(b) As per the existing orders, conveyance allowance is admissible @ 5 per cent of the basic pay subject to a maximum of Rs. 100/- p.m.

(c) No, Sir.

Irregularities in the Construction of STC Office Building

373. SHRI VIRENDRA VERMA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the construction work of office building of STC was awarded to a private company even though the CPWD was willing to undertake the work in accordance with Government rules; if so, what are the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that according to the original estimate, the work was estimated to cost Rs. 476 10 lakhs but in February, 1979 the contract for the civil work done was approved for Rs. 438 lakhs and in December, 1985 the

@Previously unstarred Question 123, transferred from the 26th December, 1989.